[2020] 12 एस.सी.आर. 128

सत्य देव @ भूरे

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 860)

07 अक्टूबर, 2020

[एस. अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना, न्यायमूर्तिगण]

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 – धारा 2(एल), 7ए, 15, 16(2), 20, 64, 69 – 2000 अधिनियम की योजना और प्रयोज्यता – अपीलकर्ता और सह-आरोपी व्यक्तियों को एफआईआर दिनांक 18 जून, 2013 में विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। 11.12.81 को धारा 302 के साथ पठित धारा 34, आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई - आरोपित फैसले द्वारा पुष्टि की गई - सह-आरोपी व्यक्तियों के संबंध में एसएलपी खारिज कर दी गई, हालांकि अपीलकर्ता के मामले में किशोर होने की दलील पर नोटिस जारी किया गया था - निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय इस स्तर पर अपीलकर्ता की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय और निर्धारण कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह 1986 के अधिनियम के तहत अपराध की तिथि पर किशोर होने के लाभ का हकदार नहीं था, और 2000 अधिनियम लागू होने पर वह वयस्क हो गया था - चूंकि 11.12.81 को अपराध के होने की तिथि पर अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिए वह किशोर के रूप में व्यवहार किए जाने और 2000 अधिनियम के अनुसार लाभ दिए जाने का हकदार है - इसके अलावा, 2015 अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के प्रकाश में, एक आरोपी को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया

जा सकता है अपराध के समय अठारह वर्ष से कम आयु का किशोर, एक अधिकार जो उसने अर्जित किया और 2000 अधिनियम के तहत फलित हुआ, भले ही अपराध 2000 अधिनियम के 01.04.2001 को लागू होने से पहले किया गया हो- 2015 अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में, 2000 अधिनियम लागू होना जारी रहेगा और उन कार्यवाहियों को नियंत्रित करेगा जो 2015 अधिनियम लागू होने पर लंबित थीं- अपीलकर्ता ने अब तक 2 वर्षों से अधिक समय तक कारावास काटा है- अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखी गई है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा को खारिज कर दिया गया है- 2000 अधिनियम की धारा 15 के तहत उचित आदेश/निर्देश पारित करने के लिए मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया जिसमें मृतक के परिवार को दिए जाने वाले जुर्माने और मुआवजे की उचित मात्रा के निर्धारण और भुगतान का प्रश्न शामिल है- किशोर न्याय अधिनियम, 1986- किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015- धारा 2, 25, 111 – सामान्य खंड अधिनियम, 1897 – धारा 6 – दंड संहिता, 1860 – धारा 302 के साथ पठित धारा 34।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 – 2015 अधिनियम की तुलना में प्रयोज्यता – चर्चा – किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 25 – क्षेत्र और अनुप्रयोग – चर्चा की गई – किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

निर्णय: 1.1 अरनीत दास बनाम बिहार राज्य और उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य के निर्णयों के तहत लंबित कार्यवाहियों पर 2000 अधिनियम के आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों के आलोक में, मामले को संविधान पीठ को भेजा

गया और प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में फैसला सुनाया गया। प्रताप सिंह में संविधान पीठ के फैसले के बाद, 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा 2000 अधिनियम में कई संशोधन किए गए। ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले 2000 अधिनियम की धारा 2(एल) को संदर्भित किया जाएगा जो "कानून का संघर्ष करने वाले किशोर" को परिभाषित करती है। 2000 अधिनियम की धारा 2 के खंड (एल) के अनुसार, अपीलकर्ता 18 वर्ष से कम आयु का होने के कारण अपराध के दिनांक को किशोर था। 2000 अधिनियम की धारा 20, जो लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान प्रदान करती है, 2006 के अधिनियम 33 के संशोधन के बाद, धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है और 2000 अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद एक सीमित गैर-बाधा या अधिभावी खंड से शुरू होती है। विधायी मंशा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है कि 2000 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर किसी भी न्यायालय में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही उस न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी जैसे कि 2000 अधिनियम पारित नहीं हुआ था। यद्यपि कार्यवाही न्यायालय के समक्ष जारी रहनी है, धारा में कहा गया है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किशोर ने अपराध किया है, तो वह निष्कर्ष को दर्ज करेगा लेकिन सजा का आदेश पारित करने के बजाय किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (बोर्ड) को भेजेगा जो तब 2000 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा, जैसे कि बोर्ड ने स्वयं जांच की थी और संतुष्ट था कि किशोर ने अपराध किया है। तथापि, शर्त में कहा गया है कि बोर्ड किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण से मामले की समीक्षा कर सकता है और किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है। 2006 के अधिनियम 33 के तहत धारा 20 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण, जो फिर से महत्वपूर्ण है, बताता है कि जिस न्यायालय में 'कार्यवाही' 'किसी भी स्तर पर' लंबित है, वह अभियुक्त की किशोरता के प्रश्न का निर्धारण करेगा। 'सभी लंबित मामलों' की अभिव्यक्ति में न केवल परीक्षण बल्कि अपील, पुनरीक्षण आदि या किसी अन्य आपराधिक

कार्यवाही के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल है। अंत में, 2000 अधिनियम उन मामलों पर भी लागू होता है जहां अभियुक्त अपराध के होने की तिथि पर किशोर था, लेकिन 2000 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर या उससे पहले किशोर नहीं रहा। ऐसे मामलों में भी, 2000 अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ये प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और अपराध किए जाने के समय सभी महत्वपूर्ण समय पर लागू थे। इस प्रकार, लंबित मामलों के संबंध में, धारा 20 अधिकारपूर्वक आदेश देती है कि न्यायालय को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि जब मामला अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा लंबित है, तब भी किशोरता के प्रश्न पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। किशोरवय का निर्धारण अपराध की तिथि पर उसकी आयु के आधार पर किया जाता है। यह तथ्य कि किशोर 2000 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर वयस्क था या बाद में वयस्कता प्राप्त कर चुका था, कोई मायने नहीं रखता। यदि अभियुक्त किशोर था, तो न्यायालय दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए भी, 2000 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और आदेश जारी करने के लिए मामले को बोर्ड को भेजेगा। [पैरा 9-11][136-ई; 137-सी-ई; 138-सीएच; 139-ए-सी]

अर्नित दास बनाम बिहार राज्य (2000) 5 एससीसी 488: [2000] 1 अनुपूरक एससीआर 69; *उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य* (1982) 2 एससीसी 202: [1982] 3 एससीआर 583; *प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य* (2005) 3 एससीसी 551: [2005] 1 एससीआर 1019 – संदर्भित।

1.2 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा, धारा 7-ए को 2000 अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसमें किशोर होने के दावे को निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। धारा 7ए 22.08.2006 को प्रभावी हुई। धारा 7ए का प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किशोर होने का दावा 'किसी भी न्यायालय' के समक्ष 'किसी भी स्तर पर' उठाया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी। जब ऐसा दावा किया जाता है, तो इसे 2000

अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही अभियुक्त 2000 अधिनियम के लागू होने पर या उससे पहले किशोर न रहा हो। इस प्रकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभियुक्त, अपराध के दिनांक को किशोर होने के बावजूद, 2000 अधिनियम के प्रारंभ होने की दिनांक 01.04.2001 से पहले या बाद में वयस्क हो गया था। वह 2000 अधिनियम के लाभ के लिए पात्र होगा। 2000 अधिनियम की धारा 64 को भी एक प्रावधान और स्पष्टीकरण को शामिल करके और मुख्य प्रावधान में 'निर्देश दे सकता है' शब्दों को 'निर्देश देगा' शब्दों से प्रतिस्थापित करके 2006 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा संशोधित किया गया था। मुख्य प्रावधान में 'निर्देश दे सकता है' शब्दों को 'निर्देश देगा' से प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रावधान अनिवार्य है न कि निर्देश। धारा 64 को नए जोड़े गए प्रावधान और स्पष्टीकरण और धारा 20 में अधिनियम 33, 2006 के तहत किए गए अन्य संशोधनों और 2000 अधिनियम में धारा 7 ए को सम्मिलित करने के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य प्रावधान में कहा गया है कि जहां कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर 2000 अधिनियम के प्रारंभ में कारावास की कोई सजा काट रहा है, उसे सजा काटने के बदले में किसी विशेष गृह में भेजा जाएगा या किसी उपयुक्त संस्थान में ऐसी रीति से रखा जाएगा जैसा राज्य सरकार सजा की शेष अवधि के लिए ठीक समझे। इसके अलावा, 2000 अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो बोर्ड ने किशोर को विशेष गृह या संस्थान में भेजने का आदेश दिया हो और अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत उसे सुरक्षात्मक देखभाल में रखने का आदेश दिया हो। परंतुक में कहा गया है कि राज्य सरकार या बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के मामले की समीक्षा करेगा जो कारावास की सजा काट रहा है और जो 2000 अधिनियम के प्रारंभ होने पर या उससे पहले किशोर नहीं रहा था और उचित आदेश पारित करेगा। हालांकि, यह स्पष्टीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां

कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर 2000 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर कारावास की सजा काट रहा है, किशोर के मामले में किशोर होने के मुद्दे सहित, धारा 2 के खंड (l) और 2000 अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य प्रावधानों और नियमों के अनुसार तय माना जाएगा, भले ही किशोर किशोर न रह गया हो। ऐसे किशोर को उसकी सजा की शेष अवधि के लिए विशेष गृह या उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसी सजा 2000 अधिनियम की धारा 15 में दी गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। कानून तय मामलों में भी दी गई सजा को रद्द और संशोधित करता है। [पैरा 12, 13][139- सी-एच; 140-ए-सी; 141-बी-जी]

1.3 यह न्यायालय इस चरण में अपीलकर्ता की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय ले सकता है और निर्धारण कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता 1986 के अधिनियम के तहत अपराध की तिथि पर किशोर होने के लाभ का हकदार नहीं था, और 2000 अधिनियम लागू होने पर वह वयस्क हो गया था। चूंकि अपीलकर्ता 11.12.1981 को अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का था, इसलिए उसे किशोर के रूप में माना जाना चाहिए और 2000 अधिनियम के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए। इससे यह न्यायालय इस प्रश्न पर पहुँचता है कि क्या किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 अधिनियम) लागू होगा, क्योंकि धारा 111 की उप-धारा (1) के अनुसार 2015 अधिनियम, 2000 अधिनियम को निरस्त करता है, यद्यपि धारा 111 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि इस निरसन के बावजूद भी 2000 अधिनियम के अंतर्गत किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई, 2015 अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा। 2000 अधिनियम की धारा 69 'निरसन और व्यावृत्ति खंड' उप-धारा (1) के समान है, जिसने 1986 अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि ऐसे निरसन के बावजूद भी 1986 अधिनियम के अंतर्गत किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई, 2000 अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा। हालांकि,

महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है 2015 अधिनियम की धारा 25, जो उस धारा के हेडनोट के अनुसार, 'लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान' को शामिल करती है। धारा 25 एक गैर-बाधा खंड है जो 2015 अधिनियम के प्रारंभ की तिथि यानी 31 दिसंबर 2015 को किसी भी बोर्ड या अदालत के समक्ष लंबित किसी बच्चे के संबंध में सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिस पर कथित रूप से कानून का उल्लंघन करने का आरोप है या पाया गया है। इसमें कहा गया है कि लंबित कार्यवाही उस बोर्ड या अदालत में जारी रहेगी जैसे कि 2015 अधिनियम पारित नहीं हुआ था। 2015 अधिनियम की धारा 25 में बोर्ड या अदालत के समक्ष 'कोई भी' शब्द का उपयोग, अपीलीय अदालत या ऐसी अदालत सहित किसी भी अदालत को शामिल करेगा जिसके समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित है। यह 'कानून का उल्लंघन करने का आरोप या पाया गया बच्चा' शब्दों के उपयोग से भी स्पष्ट है। 'पाया' शब्द का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है और यह उन मामलों में लागू होगा जहाँ कोई आदेश/निर्णय पारित किया गया हो। 'कथित' शब्द उन कार्यवाहियों को संदर्भित करेगा जहाँ कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, 2015 अधिनियम की धारा 25 बोर्ड या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसमें अपीलीय न्यायालय या वह न्यायालय शामिल होगा जहाँ पुनरीक्षण याचिका लंबित है। धारा 25 के संदर्भ में, अभिव्यक्ति 'न्यायालय' का अर्थ सिविल न्यायालय तक सीमित नहीं है, जिसे 2015 अधिनियम की धारा 2 के खंड (23) के अनुसार 'दत्तक ग्रहण' और 'संरक्षकता' के मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परिभाषा खंड तब तक लागू होता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो। धारा 25 के मामले में, विधायिका स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय का उल्लेख नहीं कर रही है क्योंकि यह धारा कथित रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले या पाए गए बच्चे के संबंध में लंबित कार्यवाही से संबंधित है, जो सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही नहीं हो सकती है। चूंकि 2015 का अधिनियम सभी लंबित कार्यवाहियों पर 2000 के अधिनियम के आवेदन की रक्षा

करता है और पुष्टि करता है, इसलिए यह न्यायालय यह नहीं मानता है कि 2015 के अधिनियम का विधायी आशय इसके विपरीत है, अर्थात 2015 के अधिनियम को सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू करना है। परिणामस्वरूप, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के साथ 2015 अधिनियम की धारा 25 के आलोक में, किसी अभियुक्त को किशोर के रूप में व्यवहार किए जाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब वह अपराध करने के समय अठारह वर्ष से कम आयु का था, यह एक ऐसा अधिकार है जिसे उसने 2000 अधिनियम के तहत हासिल किया है और उसका पालन भी किया है, भले ही अपराध 01.04.2001 को 2000 अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया हो। 2015 अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, 2000 अधिनियम उन कार्यवाहियों पर लागू होता रहेगा और उन्हें नियंत्रित करता रहेगा जो 2015 अधिनियम के लागू होने के समय लंबित थीं। (वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को इस प्रश्न की जांच करने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 2000 अधिनियम या 2015 अधिनियम लागू होगा जब अपराध 2015 अधिनियम के अधिनियमन से पहले किया गया था, लेकिन आरोप पत्र 2015 अधिनियमन के अधिनियमन के बाद दायर किया गया था। उत्तर के लिए संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) और कई अन्य पहलुओं की जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि 2015 अधिनियम कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। इन पहलुओं और मुद्दों पर बहस नहीं की गई है।) [पैरा 17, 18][146-ई-एच; 147-ए-एच; 148-ए-जी]

> *अख्तरी बी बनाम मध्य प्रदेश राज्य* (2001) 4 एससीसी 355 : [2001] 2 एससीआर 626 - पर भरोसा किया गया

1.4 विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है और न ही उस पर सवाल उठाया गया है। अपीलकर्ता अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का था और यह निर्विवाद और निर्विवाद है। अपीलकर्ता अब तक 2 वर्ष से अधिक

समय तक कारावास में रहा है। जबकि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, आजीवन कारावास की सजा को रद्द किया जाता है। मामले को बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में 2000 अधिनियम की धारा 15 के तहत उचित आदेश/निर्देश पारित करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें उचित मात्रा में जुर्माने का निर्धारण और भुगतान और मृतक के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे का सवाल शामिल है। [पैरा 21, 22][150-सी-एफ]

गौरव कुमार @ मोनू बनाम हरियाणा राज्य **(2019) 4 एससीसी 549: [2019] 3 एससीआर 372 – प्रतिष्ठित।**

धर्मबीर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य **(2010) 5 एससीसी 344 : [2010] 5 एससीआर 137;** *मुमताज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **(2016) 11 एससीसी 786 : [2016] 3 एससीआर 434;** *हरि राम बनाम राजस्थान राज्य* **(2009) 13 एससीसी 211 : [2009] 7 एससीआर 623;** *जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **(2013) 11 एससीसी 193 : [2013] 13 एससीआर 764 – पर भरोसा किया गया।**

<u>कानून पर भारोसा किया गया</u>

[2000] 1 अनुपूरक एस.सी.आर. 69	संदर्भित किया	पैरा 9
[1982] 3 एस.सी.आर. 583	संदर्भित किया	पैरा 9
[2005] 1 एस.सी.आर. 1019	संदर्भित किया	पैरा 9
[2010] 5 एस.सी.आर. 137	भरोसा किया	पैरा 14
[2016] 3 एस.सी.आर. 434	भरोसा किया	पैरा 15
[2009] 7 एस.सी.आर. 623	भरोसा किया	पैरा 16
[2001] 2 एस.सी.आर. 626	भरोसा किया	पैरा 18

[2019] 3 एस.सी.आर. 372 पृथक किया पैरा 19

[2013] 13 एस.सी.आर. 764 भरोसा किया पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 860

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के 1982 की आपराधिक अपील संख्या 994 के दिनांक 20.04.2018 के निर्णय एवं आदेश से।

अपूर्व कुरुप, निर्मल अंबष्ठ, ईशान बघेल, सुश्री उपमा भट्टाचार्जी, आशीष मैडम, सुश्री तरूणा अर्धेन्दुमौली प्रसाद, परमानंद पांडे, उत्कर्ष पांडे, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय दिया गया

संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति

1. 17.08.2018 के आदेश द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के दिनांक 20.4.2018 के निर्णय को चुनौती देने वाली केशव राम और राम कुबेर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया, हालांकि सह-अभियुक्त सत्य देव @ भूरे के मामले में किशोर होने की दलील पर नोटिस जारी किया गया था। आक्षेपित निर्णय ने केशव राम, राम कुबेर और सत्य देव को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 156/1981 दिनांक 11.12.1981 पुलिस स्टेशन गिलौला, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की थी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

2. दिनांक 02.05.2019 के आदेश द्वारा सत्य देव के मामले में अनुमति प्रदान की गई।

3. दिनांक 22.11.2019 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि वह रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री के आधार पर यह पता लगाने के लिए जांच करे कि क्या

सत्य देव घटना की तारीख यानी 11.12.1981 को किशोर था।

4. निर्देशों के अनुपालन में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच, उत्तर प्रदेश ने जांच कर दिनांक 06.03.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार, सत्यदेव की जन्म तिथि 15.4.1965 है। तदनुसार, अपराध की तिथि यानी 11.12.1981 को उसकी आयु 16 वर्ष 7 महीने और 26 दिन थी। रिपोर्ट में राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज, रामनगर खजुरी, बहराइच द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल रूप में) और प्राथमिक विद्यालय, पैरी के प्रवेश रजिस्टर का उपयोग किया गया है, जिसे क्रमशः राम नारायण सिंह इंटर कॉलेज, रामनगर खजुरी, बहराइच के क्लर्क श्री कृष्ण देव और प्राथमिक विद्यालय, पैरी की प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनुपम सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, सत्य देव ने कक्षा-10 की परीक्षा में अनुक्रमांक 9020777 के तहत भाग लिया था, तथा इस परीक्षा से संबंधित राजपत्र में दर्ज उनकी जन्मतिथि 15.04.1965 है।

5. रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई थी और परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के उत्तराधिकारियों को नोटिस दिया गया था, जो बहराइच के प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन पक्ष ने कोई सबूत पेश नहीं किया।

6. सत्य देव की जन्मतिथि निर्विवाद है और इसे हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है

7. इस निष्कर्ष के बावजूद, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच ने पाया कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) के अनुसार सत्य देव किशोर नहीं था, क्योंकि अपराध की तिथि यानी 11.12.1981 को उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी।

8. यह पहेली 1986 के अधिनियम के तहत 'किशोर' की परिभाषा के प्रकाश में है, जो लड़के के मामले में सोलह वर्ष से कम और लड़की के मामले में अठारह वर्ष से कम थी, जिस दिन लड़के या लड़की को अदालत या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहली बार पेश किया

जाता है, जबकि 2000 का अधिनियम, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, लड़के या लड़की और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है। इसके अलावा, 2000 के अधिनियम के तहत, अपराध की तारीख पर उम्र निर्धारण कारक है।

9. **अरनित दास बनाम बिहार राज्य**[1] और **उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य**[2] के निर्णयों के अनुसार, लंबित कार्यवाही में 2000 अधिनियम के आवेदन पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी विचारों के मद्देनजर, मामले को एक संविधान पीठ को भेजा गया और **प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य**[3] के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में फैसला सुनाया गया। संविधान पीठ ने निर्णय के लिए दो बिंदु तैयार किए, अर्थात्:

> "(क) क्या घटना की तारीख कथित अपराधी की किशोर अपराधी के रूप में आयु निर्धारित करने की गणना तिथि होगी या वह तारीख होगी जब उसे न्यायालय/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
>
> (ख) क्या 2000 का अधिनियम उस स्थिति में लागू होगा जब 1986 के अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो और 2000 का अधिनियम 1-4-2001 से लागू होने पर लंबित हो।"

दूसरे प्रश्न पर, संविधान पीठ ने माना कि 2000 का अधिनियम किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में 1986 के अधिनियम के तहत शुरू की गई किसी लंबित कार्यवाही में लागू होगा, यदि व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2001 को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, जब 2000 का अधिनियम लागू हुआ था। पहले प्रश्न पर, यह माना गया कि किशोर की आयु के निर्धारण के लिए गणना तिथि अपराध की तिथि है, न कि वह तिथि जब उसे प्राधिकारी के

---

1 (2000) 5 एससीसी 488

2 (1982) 2 एससीसी 202

3 (2005) 3 एससीसी 551

समक्ष या न्यायालय में पेश किया जाता है। परिणामस्वरूप, 2000 अधिनियम का प्रभाव भावी होगा, न कि भूतलक्षी प्रभाव, सिवाय उन मामलों के जहां व्यक्ति ने 2000 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। अन्य लंबित मामले 1986 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

10. **प्रताप सिंह** (सुप्रा) में संविधान पीठ के निर्णय के बाद, 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा 2000 के अधिनियम में कई संशोधन किए गए। ये संशोधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले हम 2000 अधिनियम की धारा 2(l) का संदर्भ लेंगे जो "विधि विवादित किशोर" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

> "(l) "*विधि विवादित किशोर" से ऐसा किशोर अभिप्रेत है, जिसके बारे में यह आरोप है कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।*"

2000 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (l) के अनुसार, सत्य देव 18 वर्ष से कम आयु का होने के कारण अपराध की तिथि पर किशोर था।

11. 2000 के अधिनियम की धारा 20, जो लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान प्रदान करती है, 2006 के अधिनियम 33 के संशोधन के बाद कहती है:

> "20. *लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान - इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज के होते हुए भी, किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाहियां, जिस तारीख को यह अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है, उस अदालत में जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगा और किशोर के संबंध में कोई भी सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड को भेजेगा*

जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा जैसे कि वह इस अधिनियम के तहत जांच से संतुष्ट था कि किशोर ने अपराध किया है:

बशर्ते कि बोर्ड आदेश में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण से मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

स्पष्टीकरण- किसी न्यायालय में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में विचारण, पुनरीक्षण, अपील या किसी अन्य आपराधिक कार्यवाही सहित सभी लंबित मामलों में, ऐसे किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (l) के अनुसार किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले किशोर नहीं रहा हो और इस अधिनियम के प्रावधान सभी प्रयोजनों के लिए और सभी तात्विक समयों पर लागू होंगे, जब कथित अपराध किया गया था।"

धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है और यह 2000 के अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद एक सीमित गैर-बाधा या अधिभावी खंड से शुरू होता है। विधायी मंशा स्पष्ट रूप से यह कहती है कि 2000 के अधिनियम के लागू होने की तिथि को किसी भी न्यायालय में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाहियां उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रहेंगी, जैसे कि 2000 के अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था। यद्यपि कार्यवाही न्यायालय के समक्ष जारी रहेगी, धारा में कहा गया है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किशोर ने अपराध किया है, तो वह निष्कर्ष को दर्ज करेगा, लेकिन सजा का आदेश पारित करने के बजाय किशोर को किशोर न्याय बोर्ड (बोर्ड) के पास भेज देगा, जो उसके बाद 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा,

मानो बोर्ड ने स्वयं जांच की हो और वह इस बात से संतुष्ट हो कि किशोर ने अपराध किया है। तथापि, प्रावधान में कहा गया है कि बोर्ड किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण से मामले की समीक्षा कर सकता है और किशोर के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है। 2006 की अधिनियम 33 के तहत धारा 20 में जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जो पुनः महत्वपूर्ण है, उसमें कहा गया है कि वह न्यायालय, जहां 'कार्यवाही' 'किसी भी स्तर पर' लंबित है, अभियुक्त की किशोरता के प्रश्न का निर्धारण करेगा। 'सभी लंबित मामले' में न केवल परीक्षण बल्कि अपील, पुनरीक्षण आदि के माध्यम से बाद की कार्यवाही या कोई अन्य आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है। अंत में, 2000 के अधिनियम उन मामलों पर भी लागू होता है जहां अभियुक्त अपराध की तिथि पर किशोर था, लेकिन 2000 के अधिनियम के लागू होने की तिथि पर या उससे पहले किशोर नहीं रहा। ऐसे मामलों में भी, 2000 के अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो ये प्रावधान सभी प्रयोजनों के लिए तथा अपराध किए जाने के सभी समय पर लागू थे।

इस प्रकार, लंबित मामलों के संबंध में, धारा 20 अधिकारपूर्वक आदेश देती है कि न्यायालय को किसी भी स्तर पर, यहां तक कि जब मामला अपील, पुनरीक्षण या अन्यथा लंबित हो, विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद भी, किशोरवय के प्रश्न पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। किशोरवय का निर्धारण अपराध की तिथि पर उसकी आयु के आधार पर किया जाता है। यह तथ्य कि किशोर 2000 के अधिनियम के लागू होने की तिथि पर वयस्क था या बाद में वयस्क हो गया था, कोई मायने नहीं रखता। यदि अभियुक्त किशोर था, तो न्यायालय दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए भी, 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और आदेश जारी करने के लिए मामले को बोर्ड को भेजेगा।

12. 2006 के संशोधन अधिनियम संख्या 33 द्वारा, 2000 के अधिनियम में धारा 7-ए जोड़ी गई, जिसमें किशोर होने के दावे का निर्धारण करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनाई

जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई। धारा 7ए, जो 22.08.2006 को प्रभावी हुई, इस प्रकार है:

> *"7-क. जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है, तब अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.--(1) जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है या न्यायालय की यह राय है कि कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध किए जाने की तारीख को किशोर था, तो न्यायालय जांच करेगा, ऐसे व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथ-पत्र नहीं) और यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बच्चा है या नहीं, तथा उसकी यथासंभव निकटतम आयु का कथन करेगा:*
>
> *परंतु किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकेगा और उसे किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के पश्चात भी, मान्यता दी जाएगी और ऐसा दावा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व किशोर नहीं रहा हो।*
>
> *(2) यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन अपराध किए जाने की तारीख को किशोर पाता है, तो वह किशोर को समुचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।"*

धारा 7ए का प्रावधान हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किशोर होने का दावा 'किसी भी अदालत' के समक्ष 'किसी भी स्तर पर' उठाया जा

सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी। जब ऐसा दावा किया जाता है, तो इसका निर्धारण 2000 अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, भले ही अभियुक्त अधिनियम 2000 के लागू होने के समय या उससे पहले किशोर न रहा हो। इस प्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभियुक्त, अपराध की तिथि पर किशोर था, लेकिन वह 01.04.2001 को अधिनियम 2000 के लागू होने की तिथि से पहले या बाद में वयस्क हुआ था। वह अधिनियम 2000 के तहत लाभ पाने का हकदार होगा।

13. 2000 के अधिनियम की धारा 64 को भी 2006 के अधिनियम संख्या 33 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें एक प्रावधान और स्पष्टीकरण शामिल किया गया था और मुख्य प्रावधान में 'निर्देश दे सकता है' शब्दों को 'निर्देश देगा' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था। संशोधन के बाद, धारा 64 इस प्रकार है:

> *"64. इस अधिनियम के लागू होने पर कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को सजा दी जा रही है*
>
> *किसी क्षेत्र में, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है, राज्य सरकार निदेश देगी कि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर कारावास का कोई दंडादेश भोग रहा है, ऐसा दंडादेश भोगने के बदले में, दंडादेश की शेष अवधि के लिए विशेष गृह में भेजा जाएगा या उपयुक्त संस्था में ऐसी रीति से रखा जाएगा, जैसी राज्य सरकार ठीक समझे; और इस अधिनियम के उपबंध किशोर पर इस प्रकार लागू होंगे मानो बोर्ड ने उसे, यथास्थिति, ऐसे विशेष गृह या संस्था में भेजे जाने का या इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षात्मक देखरेख में रखे जाने का आदेश दिया हो।*

परंतु, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड, किसी पर्याप्त और विशेष कारण को लेखबद्ध करके, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोर के मामले का, जो कारावास का दंडादेश भुगत रहा है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व कारावास की सजा नहीं भुगत रहा है, पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे किशोर के हित में समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- ऐसे सभी मामलों में जहां कानून का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी प्रक्रम पर कारावास की सजा भुगत रहा है, उसके मामले में, जिसमें किशोर होने का मुद्दा भी शामिल है, धारा 2 के खंड (l) और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित अन्य प्रावधानों के अनुसार तय माना जाएगा, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वह ऐसी तारीख को या उससे पहले किशोर नहीं रह जाता है और तदनुसार उसे सजा की शेष अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, विशेष गृह या उपयुक्त संस्थान में भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसी सजा किसी भी मामले में इस अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।"

मुख्य प्रावधान में 'निर्देश दे सकता है' के स्थान पर 'निर्देश देगा' शब्द प्रतिस्थापित करने का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि प्रावधान अनिवार्य है न कि निर्देशात्मक। धारा 64 को नए जोड़े गए प्रावधान और स्पष्टीकरण तथा धारा 20 में 2006 की अधिनियम 33 के तहत किए गए अन्य संशोधनों और 2000 के अधिनियम में धारा 7 ए को शामिल करने के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। मुख्य प्रावधान में कहा गया है कि जहां कानून का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर, अधिनियम 2000 के प्रारंभ में कारावास की सजा काट रहा हो, तो उसे सजा काटने के बदले में विशेष गृह में भेज दिया जाएगा या सजा की शेष अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी उपयुक्त संस्थान में रखा जाएगा।

इसके अलावा, 2000 के अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि बोर्ड ने किशोर को विशेष गृह या संस्थान में भेजने का आदेश दिया हो और अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत उसे सुरक्षात्मक देखभाल में रखने का आदेश दिया हो। प्रावधान में कहा गया है कि राज्य सरकार या बोर्ड, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण से, कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के मामले की समीक्षा करेगा, जो कारावास की सजा काट रहा है और जो 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले किशोर नहीं रहा था और उचित आदेश पारित करेगा। तथापि, यह स्पष्टीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर, अधिनियम 2000 के लागू होने की तिथि पर कारावास की सजा काट रहा है, किशोर के मामले, जिसमें किशोर होने का मुद्दा भी शामिल है, का निर्णय धारा 2 के खंड (I) तथा अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रावधानों और नियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा, भले ही किशोर अब किशोर न रहा हो। ऐसे किशोर को उसकी सजा की शेष अवधि के लिए विशेष गृह या उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसी सजा 2000 अधिनियम की धारा 15 में दी गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। यह कानून, तय मामलों में भी, दी गई सजा को रद्द करता है और उसमें संशोधन करता है।

14. इस न्यायालय ने **धरमबीर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य**[4] मामले में, वर्ष 2000 के अधिनियम की योजना और उन अभियुक्तों पर लागू होने का विश्लेषण किया था, जो अपराध के घटित होने की तिथि को अठारह वर्ष से कम आयु के थे, तथा जो वर्ष 2000 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व किया गया था, तथा यह राय और निर्णय दिया था:

> "**14.** धारा 7-ए की उपधारा (1) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि किशोर होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और उसे मामले

4 (2010) 5 एससीसी 344

के निपटारे के बाद भी किसी भी स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए तथा ऐसे दावे का निर्धारण 2000 के अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, भले ही किशोर 2000 के अधिनियम के लागू होने की तारीख को या उससे पहले किशोर न रहा हो। परंतुक का प्रभाव यह है कि कोई किशोर, जिसने अपराध किए जाने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, वह भी 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार होगा, मानो उक्त अधिनियम की धारा 2(के) के प्रावधान, जो किशोर या बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 1986 के अधिनियम के प्रवर्तन के दौरान भी हमेशा अस्तित्व में रहे हों।

15. इस प्रकार, 2000 के अधिनियम की धाराओं 2(के), 2(I), 7-ए, 20 और 49 को किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 और 98 के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति जो 1-4-2001 से पहले भी अपराध के होने की तिथि को अठारह वर्ष से कम आयु के थे, उन्हें किशोर माना जाएगा, भले ही किशोर होने का दावा उनके द्वारा 2000 के अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उससे पहले अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उठाया गया हो और वे दोषी ठहराए जाने पर सजा भुगत रहे हों। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसमें हम इस न्यायालय द्वारा हाल ही में हरि राम बनाम राजस्थान राज्य [(2009) 13 एससीसी 211: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 987] में दिए गए निर्णय से पुष्ट होते हैं।"

15. **मुमताज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[5], मामले में, कई पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने 2000 के अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव और 1986 के अधिनियम

5 (2016) 11 एससीसी 786

के साथ इसके अंतर्सम्बन्ध पर विचार किया, ताकि स्पष्ट किया जा सके:

> "**18.** *2000 के अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव पर प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य [प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य, (2005) 3 एससीसी 551: 2005 एससीसी (सीआरआई) 742] में विचार किया गया था और इसे निम्नानुसार बताया गया था: (एससीसी पृष्ठ 570, पैरा 31)*
>
>> "31. *जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, अधिनियम की धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है तथा यह गैर-बाधा खंड से शुरू होती है। यह वाक्य, 'इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी किशोर के संबंध में किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख को लंबित सभी कार्यवाहियां' बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय में किशोर के संबंध में लंबित कार्यवाही, 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई कार्यवाहियों से संबंधित है और जो 2000 के अधिनियम के लागू होने पर लंबित हैं। "किसी भी न्यायालय" शब्द में साधारण आपराधिक न्यायालय भी शामिल होंगे। यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के अंतर्गत "किशोर" था तो कार्यवाही आपराधिक अदालतों में लंबित नहीं होगी। ये मामले आपराधिक अदालतों में तभी लंबित होंगे जब लड़का 16 वर्ष या लड़की 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी होगी। इससे पता चलता है कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहां कोई व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं रह गया है, लेकिन उसने अभी तक 18 वर्ष की आयु पार नहीं की है, तो लंबित मामला उस अदालत में जारी रहेगा जैसे कि 2000 का अधिनियम पारित नहीं हुआ है और*

यदि अदालत पाती है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, किशोर को बोर्ड को भेज देगी जो उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा।"

19. *बिजेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य [बिजेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 3 एससीसी 685: 2005 एससीसी (सीआरआई) 889] में, धारा 20 के संबंध में कानूनी स्थिति निम्नलिखित शब्दों में बताई गई थी: (एससीसी पृ. 687- 88, पैरा 8-10 और 12)*:

"8. *1986 के अधिनियम और 2000 के अधिनियम के बीच बुनियादी अंतरों में से एक पुरुषों और महिलाओं की आयु से संबंधित है। 1986 के अधिनियम के तहत किशोर का अर्थ वह पुरुष किशोर है जो 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है, तथा वह महिला किशोर है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। 2000 के अधिनियम में, आयु के आधार पर किशोर लड़के और लड़की के बीच भेद नहीं रखा गया है। लड़के और लड़की दोनों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष है।*

9. *1986 के अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति किशोर नहीं माना जाता था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न कि क्या 16 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 2000 के अधिनियम के दायरे में "किशोर" माना जाता है, इसका उत्तर उसके उद्देश्य और तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए।*

10. *1986 के अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति किशोर नहीं है, उस पर किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। 2000 के*

अधिनियम की धारा 20 ऐसी स्थिति का ध्यान रखती है, जिसमें कहा गया है कि इसके बावजूद उस अदालत में मुकदमा चलता रहेगा जैसे कि वह अधिनियम पारित नहीं हुआ है और इस घटना में, वह किसी अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, उस आशय का निष्कर्ष दोषसिद्धि के फैसले में दर्ज किया जाएगा, यदि कोई हो, लेकिन किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, उसे किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") को भेज दिया जाएगा, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा जैसे कि वह जांच से संतुष्ट हो गया है कि किशोर ने अपराध किया है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान में एक कानूनी कल्पना बनाई गई है। एक कानूनी कल्पना को, जैसा कि अच्छी तरह से जाना जाता है, इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, हालांकि इसकी अपनी सीमाएं हैं।

11. ***

12. *इस प्रकार, कानूनी कल्पना के कारण, एक व्यक्ति को, यद्यपि वह किशोर नहीं है, सजा देने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा किशोर माना जाना चाहिए, जो इस स्थिति का ध्यान रखता है कि यद्यपि वह व्यक्ति 1986 के अधिनियम के अनुसार किशोर नहीं है, लेकिन फिर भी उक्त सीमित प्रयोजन के लिए 2000 के अधिनियम के अंतर्गत किशोर माना जाएगा।"*

20. *धरमबीर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [धरमबीर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2010) 5 एससीसी 344: (2010) 2 एससीसी (क्रि) 1274] में दोषसिद्धि के बाद भी किशोरवय का निर्धारण मुद्दों*

में से एक था और यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 347, पैरा 11-12)

"11. *धारा 20 के स्पष्टीकरण की भाषा से यह स्पष्ट है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण बल्कि पुनरीक्षण या अपील आदि के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (l) के अनुसार किया जाना है, भले ही किशोर 1-4-2001 को या उससे पहले किशोर न रहा हो, जब 2000 का अधिनियम लागू हुआ था, और अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी महत्वपूर्ण समयों के लिए लागू थे जब कथित अपराध किया गया था।*

12. *2000 की अधिनियम की धारा 2 के खंड (l) में प्रावधान है कि "विधि विवादित किशोर" का अर्थ है "किशोर" जिस पर कोई अपराध करने का आरोप है और जिसने ऐसे अपराध की तिथि तक अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। धारा 20 न्यायालय को नियमित न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद भी किसी व्यक्ति की किशोरता पर विचार करने और उसका निर्धारण करने में सक्षम बनाती है और न्यायालय को दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, दी गई सजा को रद्द करने और 2000 की अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा सुनाने के लिए मामले को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का अधिकार भी देती है।*"

21. *इसी प्रकार कालू बनाम हरियाणा राज्य [कालू बनाम हरियाणा राज्य, (2012) 8 एससीसी 34: (2012) 3 एससीसी (क्रि) 761] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला: (एससीसी पृष्ठ 41, पैरा 21)*

"21. *धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान करती है।*

इसमें कहा गया है कि किशोर अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी किशोर के संबंध में किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाही उस तिथि को जारी रहेगी जिस दिन किशोर अधिनियम उस क्षेत्र में लागू होता है, उस न्यायालय में इस प्रकार जारी रहेगी जैसे कि किशोर अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था और यदि न्यायालय पाता है कि किशोर ने कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे निष्कर्ष को दर्ज करेगा और किशोर के संबंध में कोई सजा सुनाने के बजाय किशोर को बोर्ड के पास भेजेगा जो किशोर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा जैसे कि किशोर अधिनियम के तहत जांच से उसे संतुष्टि हो गई हो कि किशोर ने अपराध किया है। धारा 20 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण बल्कि पुनरीक्षण या अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (l) के अनुसार होगा, भले ही किशोर 1-4-2001 को या उससे पहले किशोर न रहा हो, जब किशोर अधिनियम लागू हुआ था, और किशोर अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों और सभी भौतिक समयों के लिए लागू थे जब कथित अपराध किया गया था।"

16. कानून और सिद्धांत की इस स्थिति की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा पहली बार **हरि राम बनाम राजस्थान राज्य**[6] मामले में निम्नलिखित शब्दों में की गई थी:

"**39.** *वर्ष 2006 में जो स्पष्टीकरण जोड़ा गया था, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण बल्कि पुनरीक्षण या*

6 (2009) 13 एससीसी 211

अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल है, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (एल) के अनुसार किया जाएगा, भले ही किशोर 1-4-2001 को या उससे पहले किशोर न रहा हो, जब किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लागू हुआ था, और अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त प्रावधान सभी प्रयोजनों के लिए और सभी भौतिक समयों के लिए लागू थे, जब कथित अपराध किया गया था। वस्तुतः, धारा 20 न्यायालय को नियमित न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद भी किसी व्यक्ति की किशोरता पर विचार करने और उसका निर्धारण करने का अधिकार देती है, तथा न्यायालय को दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, दी गई सजा को रद्द करने और किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सजा सुनाने के लिए मामले को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजने का अधिकार भी देती है।"

17. ऊपर वर्णित कानूनी स्थिति और उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यह न्यायालय इस स्तर पर सत्य देव की किशोरता के प्रश्न पर निर्णय ले सकता है और उसे निर्धारित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि सत्य देव 1986 के अधिनियम के तहत अपराध की तिथि पर किशोर होने के लाभ का हकदार नहीं था और 2000 के अधिनियम लागू होने पर वह वयस्क हो गया था। चूंकि सत्य देव 11.12.1981 को अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का था, इसलिए उसे किशोर के रूप में माना जाना चाहिए और 2000 के अधिनियम के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए।

18. इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 अधिनियम) लागू होगा, क्योंकि धारा 111 की उपधारा (1) के अनुसार 2015 के अधिनियम, 2000 के अधिनियम को निरस्त करता है, यद्यपि धारा 111 की उपधारा (2) में कहा गया है कि इस निरसन के बावजूद, 2000 के अधिनियम के तहत

किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई, 2015 के अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी। 2000 के अधिनियम की धारा 69 'निरसन और व्यावृत्ति खंड' उसी के समान है, क्योंकि इसकी उपधारा (1) ने 1986 अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि ऐसे निरसन के बावजूद 1986 अधिनियम के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या किया गया कार्य 2000 के अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया माना जाएगा। हालाँकि, हमारे लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है 2015 के अधिनियम की धारा 25, जो उस धारा के शीर्षक के अनुसार, लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान को शामिल करती है और कहती है:

> "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी बालक के संबंध में, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वह विधि का उल्लंघन करता है या पाया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां, उस बोर्ड या न्यायालय में उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं हुआ था।"

धारा 25 एक गैर-बाध्यकारी धारा है जो कानून का उल्लंघन करने वाले कथित बालक[7] के संबंध में सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है जो अधिनियम, 2015 के लागू होने की तिथि अर्थात 31 दिसंबर, 2015 को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसमें कहा गया है कि उस बोर्ड या न्यायालय में लंबित कार्यवाही उसी तरह जारी रहेगी जैसे कि 2015 का अधिनियम पारित नहीं हुआ था। **अख्तरी बी बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[8] में, यह देखा गया कि अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसलिए अपील के लंबित रहने के दौरान विचारण न्यायालय का फैसला अंतिम नहीं होता है और इस उद्देश्य के लिए

---

7 2015 अधिनियम की धारा 2 के खंड (12) के अनुसार 'बच्चा' शब्द का अर्थ है - 'ऐसा व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।'

8 (2001) 4 एससीसी 355

दोषसिद्धि के बावजूद ट्रायल जारी माना जाता है। इस प्रकार, 2015 के अधिनियम की धारा 25 में बोर्ड या न्यायालय के समक्ष 'किसी' शब्द का प्रयोग, अपीलीय न्यायालय या ऐसी अदालत जिसके समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित है, सहित किसी भी न्यायालय को संदर्भित करेगा। यह बात 'ऐसा बच्चा जिसके बारे में आरोप है कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है या पाया गया है' शब्दों के प्रयोग से भी स्पष्ट है। शब्द 'पाया' का प्रयोग भूतकाल में किया गया है और यह उन मामलों में लागू होगा जहां कोई आदेश/निर्णय पारित किया गया हो। 'कथित' शब्द का तात्पर्य उन कार्यवाहियों से है जहां कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा, 2015 के अधिनियम की धारा 25 बोर्ड या अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसमें अपीलीय अदालत या वह अदालत जहां पुनरीक्षण याचिका लंबित है, सहित कोई भी अदालत शामिल होगी। धारा 25 के संदर्भ में, अभिव्यक्ति 'न्यायालय' का अर्थ सिविल न्यायालय तक सीमित नहीं है, जिसके पास 2015 के अधिनियम[9] की धारा 2 के खंड (23) के अनुसार 'दत्तक ग्रहण' और 'संरक्षकता' के मामले में क्षेत्राधिकार है। परिभाषा खंड तब तक लागू होता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। धारा 25 के मामले में, विधानमंडल स्पष्ट रूप से सिविल न्यायालय का उल्लेख नहीं कर रहा है, क्योंकि यह धारा ऐसे बच्चे के संबंध में लंबित कार्यवाही से संबंधित है, जिसके बारे में आरोप है कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है या पाया गया है, जो सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही नहीं हो सकती। चूंकि 2015 का अधिनियम सभी लंबित कार्यवाहियों पर 2000 के अधिनियम के लागू होने की रक्षा करता है और इसकी पुष्टि करता है, इसलिए हम यह नहीं मानते कि 2015 के अधिनियम का विधायी उद्देश्य इसके विपरीत है, अर्थात 2015 के

---

9 "(23) – "न्यायालय" से सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जिसे दत्तक ग्रहण और संरक्षकता के मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त है और इसमें जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय और शहर के सिविल न्यायालय शामिल हो सकते हैं';"

अधिनियम को सभी लंबित कार्यवाहियों पर लागू करना है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 जो किसी अधिनियम के "निरसन" के परिणाम प्रदान करती है, कहती है:

> 6. ***निरसन का प्रभाव-*** *जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियमन, अब तक बनाए गए या इसके पश्चात बनाए जाने वाले किसी अधिनियम को निरस्त करता है, वहां जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, निरसन:*
>
> *xxx*
>
> *(ग) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता को प्रभावित नहीं करेगा;*

परिणामस्वरूप, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित 2015 के अधिनियम की धारा 25 के आलोक में, किसी अभियुक्त को किशोर के रूप में व्यवहार किए जाने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब वह अपराध के समय अठारह वर्ष से कम आयु का था, यह एक ऐसा अधिकार है जिसे उसने 2000 के अधिनियम के तहत अर्जित किया है और उसका पालन भी किया है, भले ही अपराध 01.04.2001 को 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया हो। 2015 के अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, 2000 के अधिनियम लागू रहेगा तथा उन कार्यवाहियों को नियंत्रित करेगा जो 2015 के अधिनियम के लागू होने के समय लंबित थीं। (वर्तमान मामले में, हमें इस प्रश्न की जांच करने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या 2000 अधिनियम या 2015 अधिनियम लागू होगा जब अपराध 2015 अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले किया गया था, लेकिन आरोप-पत्र 2015 अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद दायर किया गया था। इसके उत्तर के लिए संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (1) और कई अन्य पहलुओं की

जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि 2015 का अधिनियम कानून से संघर्षरत बच्चों के संबंध में पूरी तरह से अलग व्यवस्था और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। इन पहलुओं और मुद्दों पर हमारे समक्ष बहस नहीं की गई है।)

19. **गौरव कुमार उर्फ मोनू बनाम हरियाणा राज्य**[10] में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर राज्य के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, कोई लाभ नहीं पहुंचाता क्योंकि यह निर्णय आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 की व्याख्या और अनुप्रयोग पर है। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है और न ही उस पर प्रश्न उठाया गया है। हम पुनः यह दर्ज करना चाहेंगे कि अपराध की तिथि पर सत्यदेव की आयु 18 वर्ष से कम थी और यह निर्विवाद एवं निर्विवाद है।

20. सत्य देव अब तक दो साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं। **मुमताज उर्फ़ मुंतयाज** (सुप्रा) मामले में, उस व्यक्ति को दी जाने वाली सजा की प्रकृति और परिमाण से संबंधित, जो अपराध किए जाने की तिथि पर किशोर था, इस न्यायालय ने, **जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[11] के पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, कहा था:

> **22.** *इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित है कि 2000 के अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त घटना की तिथि पर 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का था, न्यायालय में लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और तार्किक निष्कर्ष तक ले जाई जाएगी, इस अपवाद के अधीन कि किशोर को दोषी पाए जाने पर न्यायालय उसके विरुद्ध सजा का आदेश पारित नहीं करेगा, बल्कि किशोर को 2000 के अधिनियम के तहत*

---

10 (2019) 4 एससीसी 549

11 (2013) 11 एससीसी 193

उचित आदेश के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा। ऐसे मामले में किस तरह का आदेश पारित किया जा सकता है, जहां वर्तमान मामले के समान स्थिति में किशोर होने का दावा स्वीकार किया गया हो, इस पर इस न्यायालय ने जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 11 एससीसी 193: (2013) 4 एससीसी (क्रि) 725] में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया था: (एससीसी पृ. 210-11, पैरा 32)

> "32. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत दिए गए "दंड" के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए, उसे सलाह देना या चेतावनी देना [खंड (ए)] शायद ही कोई "दंड" हो सकता है जिसे दिया जा सके क्योंकि यह अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार, उसकी लगभग 40 वर्ष की आयु को देखते हुए, यह अपेक्षा करना पूरी तरह से भ्रामक है कि अपीलकर्ता को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाएगा, किसी माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जाएगा [खंड (बी)]। इसी कारण से, अपीलकर्ता को किसी उपयुक्त संस्थान [खंड (सी)] की देखरेख में अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जा सकता है और न ही उसे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 10 के तहत विशेष गृह में भेजा जा सकता है, जिसका उद्देश्य अपराधी किशोरों के पुनर्वास और सुधार के लिए है [खंड (डी)]। इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता को दी जाने वाली एकमात्र यथार्थवादी सजा यह है कि उसे किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 21(1) के खंड (ई) के तहत जुर्माना अदा करने के लिए कहा जाए।"

21. उपर्युक्त अनुपात और ऊपर स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति का अनुसरण करते हुए, हम सत्य देव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, आजीवन कारावास की सजा को अपास्त करते हैं। हम इस मामले को बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भेजेंगे ताकि वह अधिनियम 2000 की धारा 15 के अंतर्गत उचित आदेश/निर्देश पारित कर सके, जिसमें जुर्माने की उचित राशि का निर्धारण और भुगतान तथा मृतक के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे का प्रश्न भी शामिल है। हम 2000 के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आदेश/निर्देश पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं।

22. तदनुसार, हम जेल प्राधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के भीतर सत्यदेव को बोर्ड के समक्ष पेश करें। इसके बाद बोर्ड नजरबंदी और हिरासत के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा और उसके बाद 2000 के अधिनियम के तहत आदेश/निर्देश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

23. सत्य देव द्वारा दायर अपील को उपरोक्त शर्तों के साथ आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत